recoveries. An on account release of Rs. 250 crores will be made pending further discussion between Planning Commission and the Ministry of Finance.

(ii) The Planning Commission will provide additional funds to the State Government for "Dal Lake Conservation Plan" as well as reconstruction fof damaged infrastructure in a phased manner.

(iii) The State Govt. will be released SRE funds in advance on pro-rata monthly instalments, which will be adjusted against the State Government's claim.

(c), (d) and (e)

For North Eastern States including Assam, various initiatives have been taken for their accelerated economic development. These include, *inter-alia*;

1. Economic package announced by PM for NE States in October, 1996.
2. Rs. 131.91 crores released as reimbursement of additional security related expenditure to the Government of Assam for the period 1990-95.
3. New Industrial Policy for NE announced in 1997.
4. Royalty on oil revised.

Economic reliefs for J&K

3902. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the centre is contemplating announcement of major econoimc reliefs for Jammu and Kashmir;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the modalities of implementing them?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c) In a high level meeting taken by the Home Minister with the Chief Minister, J&K on 5th July 1998 where Deputy Chairman, Planning Commission and the Finance Minister were present, it was agreed that the Govt. of India would meet the Plan requirements of the State by bridging the resource gaps and thus provide funding for a suitable Plan size. However, the State Government will also take steps to improve their own resources by better collection of revenues/recoveries. Following the high level meeting, "on account" release of Rs. 250 crores has been made, pending further discussion between Planning Commission and the Ministry of Finance.

It was also decided during the meeting that the Planning Commission would provide additioinal funds to the State Government for Dal Lake Conservation Plan as well as reconstruction of damaged infrastructure in a phased manner.

In addition, the State Government will also be released SRE funds in advance on *pro-rata* monthly instalments, which will be adjusted against the State Government's claim.

देश में बिजली की कमी

3903. श्री रामजी लाल: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है और इसमें से केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संस्थानों द्वारा क्रमशः कितना-कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) इस समय देश में बिजली की कुल कितनी कमी है तथा इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने विद्युत की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए है और उनके परिणाम कब तक मिलने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम): (क) अप्रैल-जून, 1993 के दौरान देश में उत्पादित ऊर्जा का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

(आंकड़ें मिलियन यूनिट में)

क्षेत्र	उत्पादन का प्रकार	उत्पादन
केन्द्रीय क्षेत्र	ताप	33378
	न्यूक्लीय	2472
	जल	7550
	जोड़	43400
राज्य क्षेत्र	ताप	48001
	जल	12452
	जोड़	60453
निजी क्षेत्र	ताप	7391
	जल	248
	जोड़	7639
अखिल भारत	ताप	88770
	न्यूक्लीय	2472
	जल	20250
जोड़		111492

(ख) अप्रैल-जून, 1998 के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) सरकार ने देश में विद्युत स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत कानूनों में संशोधन, राज्य विद्युत बोर्डों का पुर्नगठन केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के लिए उच्च बजटीय आबंटन, विद्युत केन्द्रों का नवीकरण और आधुनिकीकरण, राज्य क्षेत्र की निर्माणाधीन परियोजनाओं जो शीघ्र पूरा करने के लिए ब्याज संबंधी आर्थिक सहायता, नवीकरण व आधुनिकीकरण तथा प्रणाली सुधार, वृहत् परियोजनाओं के लिए नीति निर्माण, क्षेत्रीय एकीकृत प्रचालन का संवर्धन और अंतर-राज्यीय/क्षेत्रीय विद्युत अंतरण को अधिकतम करना और विद्युत प्रणाली की रूपातरण क्षमता और पारेषण का संवर्धन शामिल है।

विवरण

विद्युत आपूर्ति का वास्तविक स्थिति

सभी आंकड़े मि॰ यू॰ निवल में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	अप्रैल, 98 से जून, 98			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	270	267	3	1.1
दिल्ली	4280	4149	131	1.1
हरियाणा	3570	3397	173	4.8
हिमाचल प्रदेश	696	696	0	0.0
जम्मू और कश्मीर	1315	1293	22	1.7
पंजाब	7015	6639	376	5.4
राजस्थान	5425	5212	213	3.9
उत्तर प्रदेश	10795	9806	989	9.2
जोड़ (उ॰ क्षे॰)	33366	31459	1907	5.7

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	अप्रैल, 98 से जून, 98			
	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	%
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	11628	10930	698	6.0
मध्य प्रदेश	8221	7857	364	4.4
महाराष्ट्र	16771	16270	501	3.0
गोवा	364	364	0	0.0
जोड़ (प० क्षे०)	36984	35421	1563	4.2
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	10324	9156	1168	11.3
कर्नाटक	6639	5551	1088	16.4
केरल	3075	2726	348	11.3
तमिलनाडु	9919	8296	1623	16.4
जोड़ (द० क्षे०)	29957	25732	4425	14.1
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	2110	1914	196	9.3
डी० वी० सी०	1864	1954	-90	4.8
उड़िसा	2525	2555	-30	-1.2
पश्चिमी बंगाल	4018	4146	-128	-3.2
जोड़ (पू०क्षे०)	10517	10559	-42	-0.4
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र				
अरूणाचल प्रदेश	36.3	28.6	7.7	21.2
असम	763.0	675.2	87.8	11.5
मणिपुर	125.8	114.8	11.0	8.7
मेघालय	98.7	105.1	-6.4	6.5
मिजोरम	53.6	44.3	-9.3	17.4
नागालैंड	51.9	41.6	10.3	19.8
त्रिपुरा	132.7	127.4	5.3	4.0
जोड़ (उ० पू० क्षे०)	1262.0	113.7	125.0	9.9
अखिल भारत	112086	104308	7778	6.9

कहलगांव के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

3904. **श्री जनार्दन यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) थर्मल पावर कहलगांव द्वारा अब तक कितने विस्थापितों का पुनर्वास किया गया;

(ख) ऐसे विस्थापित परिवारों में से कितने परिवारों के सदस्यों को नौकरी दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश परिवारों को नौकरी नहीं दी गई है जिससे भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई; और